



करंट क्राइम

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

सिर्फ सच...

● नई दिल्ली। बुधवार 02 जुलाई-2025

● गर्ष: 10 अंक: 193 पेज-08

● RNINo.DELHIN/2015/65364

● मूल्य: ₹3



जिन्नेदारी



गाजियाबाद (करंट क्राइम)। आईएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह यमुना एक्सप्रेस औरोपिंग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्रवाई रंभाल लिया। आकर्षण सिंह गाजियाबाद में जिलाधिकारी के पद पर कार्रवाई रहे हैं। उनकी गिनती कुशल प्राप्तकर तथा जन समस्याओं के लिए नियन्त्रण करने वाले अधिकारियों में होती है।

सिटी जोन के नौ शातिर अपराधियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट, 9 आरोपियों पर दर्ज है 56 मुकदमे

गाजियाबाद, करंट क्राइम: पुलिस कमिशनरेट गाजियाबाद वाले सिस्टम में अपराधियों पर अर्थ उनपर पकड़ भर्जूत करने के लिए कमिशनरेट पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कमिशनर जे रविंदर गोड़ के नियंत्रण पर डीसीपी सिटी जोन धब्ल जारीबाल द्वारा 9 शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इताया जा रहा है इन सभी नौ आरोपियों पर कुल 56 मुकदमे दर्ज हैं। कम्पल से लेकर राहुल तक की खोली गई हिस्ट्रीशीट: डीसीपी सिटी जोन धब्ल जारीबाल ने जानकारी दी कि थाना नंदगाम के कार्रवाई का लिया और विमान एवं पैदली थाना विजयगढ़र से अद्वृत कालाम, अभय उर्फ ओम पूर्णी, गुलजार सिंहीकी को मधुबन्ध बाष्पाम से अपित उर्फ अनुज उर्फ गाल दीपक राजा शमी का अविवेद शमी और थाना शिवहानी गेट के राहुल कुमार की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इन सभी पर दो और उनसे अधिक मुकदमे दर्ज थे।



हर 800 मीटर पर तैनात रहेगा एक उपनिशेक



गाजियाबाद, करंट क्राइम: पुलिस कमिशनरेट गाजियाबाद वाले सिस्टम में कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। तो खुद पुलिस कमिशनर से लेकर जिलाधिकारी सड़कों पर उत्तर कर होकीत जान रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस कमिशनरेट गाजियाबाद को वाले सिस्टम में दिल्ली-नोएडा पुलिस और गाजियाबाद के शीर्ष अधिकारियों को आईडिनेशन मीटिंग होनी है। तो वहीं पुलिस कमिशनरेट गाजियाबाद के सुनों से जानकारी मिली है कि इस बार हफ्ते दिन दो गाजियाबाद पुलिस में कांवड़ यात्रा बीट पुलिस कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रा बीट पुलिस



के द्वारा सुरक्षा की कमान संभाल ली जाएगी। इसके साथ ही हर 800 मीटर की दूरी पर एक उपनिशेक और एक हेड कास्टेबल व कास्टेबल तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ी अलग-अलग द्वारा पांडिंग पर तैनात किए जाएंगे। 112 जुलाई से सावन माह शुरू हो रहा है। तो कांवड़ यात्रा में 20 तारीख के आसपास भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी रूट डॉयलजन का प्लान फाइनल नहीं किया गया है।

वॉच टावर पर हथियारों से लैस

रहेंगे पुलिसकर्मी

करंट क्राइम: पुलिसल सीपी आलोक प्रियदर्शी जो कांवड़ यात्रा को प्रमुखता से सभाल रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कांवड़ रूट यार्ड पर लाग्ग 60 से अधिक वॉच टावर बनाए जाएंगे। जिनमें पुलिस कर्मियों की रथ थानाक्षेत्र में डूट्यू रहेंगे। वॉच टावर पर तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों के पास दूरबीन, टॉर्च, हथियार और कंट्रोल रूम से लेकर वारलेस सिस्टम रहेंगे ताकि वह हर गतिविधि को लेकर अपडेट करते रहे हैं।

100 से अधिक पुलिसकर्मी धारण करेंगे भोले का भेष

करंट क्राइम: गाजियाबाद वाले सिस्टम के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता थानाक्षेत्र में दो ऐसे पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो भोले के भेष में रहकर कांवड़ यात्रा के दौरान नजर रखने का काम करेंगे। आपत स्थिति में रिस्ट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर रहेगी। इसके लिए प्रयोक्ता थानाक्षेत्रों के दो ऐसे पुलिसकर्मी जो कांवड़ कंट्रोल से लेकर नेटवर्किंग में एक साथ ही उनको लाभार्थी बताया जा रहा है यह कांवड़ ड्यूटी के दौरान ना तो दबी बनवाएंगे और ना ही पुलिस की वर्दी धारण करेंगे। हड़ कड़ महत्वपूर्ण इनपुट जुलाई का भी काम करेंगे।



सर्किल अफसर और थाना प्रभारी रोजाना कांवड़ मार्ग पर देंगे इयूटी

करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा शुरू होने के दौरान प्रयोक्ता स्थान के अधिकारी और थाना प्रभारी को भी फील्ट पर कांवड़ यात्रा में डूट्यू देनी होगी। इसके लिए उनके क्षेत्र में आने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर एसीपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा की कमान संभालने का काम करेंगे।

शरारती तत्वों पर निगरानी रखेंगी सोशल मीडिया सेल और कंट्रोल रूम

करंट क्राइम: मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा सभी कमिशनर, पुलिस कासान और प्रमुख अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए निर्देश दिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया सेल के जरिए भी शरारती तत्वों पर निगरानी रखने का काम होगा। ताकि किसी प्रकार की गडबड़ी और दिक्कत ना आए।

पांच विभागों को 20 दिन में पूरे करने हैं अधूरे काम

कांवड़ मार्ग पर कहीं है अंधेरा, तो कहीं दूटी सड़क और जलभराव

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस-प्रोजेक्ट-प्राप्तकर्ता कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ प्राप्तकर्ता की गई है। बीते नदर से एफएसए में सेकेटर रेनोर रेनोर रेपिड दिनों गाजियाबाद में सेकेटर रेनोर रेपिड अधिकारियों का नियंत्रण और नियंत्रण और सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई है। कृष्ण सागर अगले 20 दिनों के भीतर कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

जलभराव की समस्या को समर्याएं जीवन से बचाएंगे। जीवन से बचाएंगे।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की समस्या नहीं होनी चाहिए।

गाजियाबाद, करंट क्राइम: कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के मार्ग पर कांवड़ यात्रा की सम

केंद्र ने कई योजनाओं को दी मंजूरी योजगाए से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के एप्लॉयमेंट लिंक्ड इसेंट्रिप (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना खासगत पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेंगी। और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे योजना को जुड़ी रुपये की मंजूरी दी है।



परमुंडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना : सरकार ने भी मंगलवार को रोजगार सृजन, कौशल बढ़ावा और देने वाली कपणियों को समर्पण देने के लिए होगा। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और

जाएगा। प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों तक दी जाएगी वह प्रोत्साहन उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे जिनका बेतन 1 लाख रुपये के लिए प्रतिमाह तक है। नियन्य धन्यवाच के लिए होगा।

शोध और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़

सरकार ने देश में शोध, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए तरत 1.07 लाख करोड़ का प्रोत्साहन किया जाएगा। योजना को मंजूरी दी है।

जानकारी के अनुसार, हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ इलाके के कुचेसर रोड चैपला स्थित राजा जी हवेली में घटना समेवार रात साथे दस बजे हुई है।

बुलदार्ह जिले के फगदपुर का रहने वाला बुकबुक बाइक से प्रेमिका का बर्थ-डे विश करने के लिए होटल में पहुंचा था। यहाँ कुर्सी पर बैठने से एक बुकबुक की मौत हो गई। कार ने चार लोगों को रोटी दी है। हादसे में एक बुकबुक की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका समेत तीन लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ इलाके के कुचेसर रोड चैपला स्थित राजा जी हवेली में घटना समेवार रात साथे दस बजे हुई है।

बुलदार्ह जिले के बाद कार चालक फगदपुर का रहने वाली बाताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फरार बताकर आया था कि वह युवती होने का बर्थ-डे पार्टी में शामिल होने वाली थी। युवती को परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों ने मामले में हात्या की गई है।

अजितपाल की मौत पर ही मौत हो गई। जबकि प्रेमिका समेत दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

हादसे के बाद कार चालक फगदपुर हो गया। मृतक दिल्ली जल बोर्ड में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फरार बताकर आया था कि वह युवती होने का बर्थ-डे पार्टी में शामिल होने वाली थी। युवती को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है।

प्रेमिका गढ़-दुर्ग रेस्टोरेंट के अधिक पदों पर लागू हुआ।

आरक्षण कोट्ट का एतिहासिक कदम

पहली बार स्टाफ के लिए हुई आरक्षण नीति लागू

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुमूलिक जाति और अनुसूचित जनजाति के उमीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्ति और प्रमोशन में अरक्षण का लाभ मिलेगा।

गैर न्यायिक पदों पर लागू हुआ

आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामाकाज में बड़े बदलाव का संकेत है।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ही क्यों अपवाद रहे ? : आरक्षण नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पढ़ाई द्वारा की गयी थी। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के अधिकारी और अधिकारी ने इसकी विवरण दिया है।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ही क्यों अपवाद रहे ? : आरक्षण नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पढ़ाई द्वारा की गयी थी। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के अधिकारी और अधिकारी ने इसकी विवरण दिया है।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।



कर्ट्राइम

सिर्फ सच...

103

• नई दिल्ली। बुधवार 02 जुलाई - 2025

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

मले ही निकली निगम में प्रस्ताव के निरस्त वाली झाँकी है हालात बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। नगर निगम में विशेष बोर्ड बैठक हुई और सोन में राजस्व की जगह है शासन में मामला है और शासन की भी राजस्व वाले सीन में तंग नहीं होना चाहता। जिलों में कलेक्टर का काम ही राजस्व का कलेक्टर करता है और इस कलेक्टर के लिये अलग-अलग विभाग अपने-अपने तरीके से कलेक्टर करते हैं। कोई सड़क पर खड़ा होकर राजस्व के लिये काम करता है, इसमें परिवहन विभाग से लेकर जीएसटी के लोग शामिल हैं और राजस्व का एक काम बंद करते हैं नीतियों से तय होता है।

ये राजस्व का तरीका है। वहाँ दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राजस्व कोई पहली बार लागू नहीं हुआ है और कोई पहली बार वसूला भी नहीं जा रहा है, लेकिन लोकहित को सर्वोंपर रखा जाना चाहिए। उदाहरण दिया जा रहा है प्राचीन जाना भी लगान के जरिये टैक्स लगाते थे और तब वाले को लेकर ये बात रहती थी कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए मगर, नगर निगम में तो दस ग्रा तक टैक्स बढ़ गया और इस टैक्स के विरोध में पार्सद आ गए और फिर बढ़े हुए टैक्स के विरोध में बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में टैक्स बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव नहीं गया।

पार्सद थेरें से लेकर सर्वसंघ थेरें तक जय-जयकर होने लगी, लेकिन सूख बताते हैं कि ज्यादा उत्साहित होने से बचाना होगा। वो बता रहे हैं कि जो प्रस्ताव इस साझेने के लिये प्रतेशेषक में जाना होगा। 2024 में जब प्रतेश निरस्त हो गया तो इस प्रस्ताव को निगम प्राप्तानन ने शासन को भेजा। उससे पहले की कठानी 2022 से जुड़ी है। 2022 में तत्कालीन नगरायुक्त महेंद्र रिंग तंवर ने डीएम सर्किल रेट पर हाउस टैक्स लागू करने का प्रस्ताव दिया। पार्सद ने मर्मांखोल दिया और तब भी पार्सद ने उनसे डाटा मांगा और तब भी ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया। बताया जाता है कि शासन ने इस प्रस्ताव का ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शासन सरकार की मान लिया जाना चाहिए और सूख बता रहे हैं कि पिक्चर



उत्तर समय शासन ने तय किये थे तीन मानक

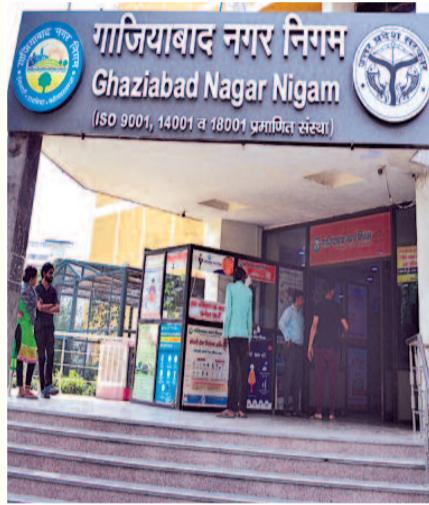
करंट क्राइम। कठानी राजस्व से है और यहाँ पर बताया ये जाता है कि उत्तर समय शासन से ये निर्देश मिले थे कि सेक्शन 104 (ख) नगर निगम की ओर से आया। इसमें बताया गया कि डीएम सर्किल रेट की दों एक अप्रैल 2024 से लागू की जाती है। इस विज्ञापन के बाद पता चला कि 2023 में जो शर्ट रखी गई थीं वो इस फॉर्मेट से गया थे। जब ये विज्ञापन आया तो नगर निगम की नई कार्यकारियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जब पिछला सदन दस प्रतिशत टैक्स बढ़ा चुका है तो अब यह हमें रखीकर नहीं है। इसके बाद नगर निगम ने नई दरों पर नई सम्पत्ति पर नया पार्सुर्मा लागू किया। फिर जो शोर मचा वो अभी तक मच रहा है।

तब नी हुई थी प्रतिशत में किटाया बढ़ाने की बात, नीहीं थी गुणा में वृद्धि की बात

करंट क्राइम। वर्ष 2023 में जो बैठक हुई थी जो बैठक थी और सूख बताते हैं कि इस बैठक में भी दस प्रतिशत हाउस टैक्स दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया। दूसरा फॉर्मूला यह था कि बाजार में प्रतिशत किये दर के हिसाब से तय किया जाए और तीसरे फॉर्मूला में अन्य कारण बताए थे और अन्य कारण तय करना का अधिकार बोर्ड का दिया गया। जिसमें कहा गया है कि बोर्ड जो तय करे। तीनों में से जो भी कम हो उसे लागू करने की बात थी। वर्ष 2022, वर्ष 2023 आया और यही निर्वश रिपीट हो गए। तब जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि प्रत्येक दो वर्ष में कियारा बढ़ाना था और इसे बैठक बताया गया था।

जब अखबारों में विज्ञापन आया तो मामला सामने आया

करंट क्राइम। सूत्र बताते हैं कि दस प्रतिशत वृद्धि की बात थी, समय तय हो गया था लेकिन 9 जनवरी 2024 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन की ओर से आया। इसमें बताया गया कि डीएम सर्किल रेट की दों एक अप्रैल 2024 से लागू की जाती है। इस विज्ञापन के बाद पता चला कि 2023 में जो शर्ट रखी गई थीं वो इस फॉर्मेट से गया थे। जब ये विज्ञापन आया तो नगर निगम की नई कार्यकारियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जब पिछला सदन दस प्रतिशत टैक्स बढ़ा चुका है तो अब यह हमें रखीकर नहीं है। इसके बाद नगर निगम ने नई दरों पर नई सम्पत्ति पर नया पार्सुर्मा लागू किया। फिर जो शोर मचा वो अभी तक मच रहा है।



स्टेटलों है वार्ड नगर, अभी बाकी है जगनींट ऑफ नी-लॉर्ड

करंट क्राइम। सूत्र बताते हैं कि कठानी डीएम सर्किल रेट निरस्त होने के बाद शुरू हुई और तब भी मंत्री-विधायक बैठक में थे और रिश्ति एक बार फिर वही नगर निगम की ओर से आया। इसके बाद शुरू हुआ है। लेकिन कठानी में अभी मी-लॉर्ड बाकी हैं। वो बता रहे हैं भले ही सदन में निरस्त वाली झाँकी निकली है, लेकिन पिक्चर बाकी है और जगनींट तो मी-लॉर्ड को ही बताना है। 29 जुलाई की तरीख इस मामले में 30 अप्रैल है। योंके 29 जुलाई की अदालत में इस केस की सुनवाई होनी है। इसलिये कठानी में कोई भी मोड आ सकता है। मामला कोर्ट में है और जाहिर है कि नगर निगम के अधिकारी भी अपना पक्ष रखने के लिये कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ पहुंचेंगे, तो पिक्चर 29 जुलाई तक बाकी है। योंके अभी पूरा मामला कोर्ट के फैसले पर टैक्स बढ़ा। और अगर अब सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त हुआ तो इसकी क्या गारंटी है।

पूर्व पार्श्व कर रहे हैं बोर्ड बैठक की मिनट्स बुक का इंतजार

करंट क्राइम। सूत्र बताते हैं कि कठानी एण्ड नीहीं हुई है। दोनों ही बाध तयारियों के साथ हैं और जहाँ कठानी में कोर्ट वाला मोड आ रहा है वही बताया ये भी जा रहा है कि जिन पूर्व पार्श्वों ने सबसे पहले मोर्चा खोला था उनकी तरफ से प्रस्ताव निरस्त होने के बाद भी सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व पार्श्व 30 जून वाली बैठक के मिनट्स तालिका रहे हैं। वो उसी मिनट्स के आधार पर आगे की रणनीति बनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि सात मार्च 2025 को बौद्ध बैठक हुई थी, उस बैठक में सबसे पहले प्रस्ताव संस्था-117 लाया गया था और इसका मतलब यह है कि पूर्व की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हुई है। अब यही पूछा जा रहा है कि जब तब प्रस्ताव निरस्त हो गया तो फिर किस आधार पर टैक्स बढ़ा। और अगर अब सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त हुआ तो इसकी क्या गारंटी है।

मिजोरम से रथी जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद बात

नितिन गडकरी को लिखा पत्र और की गाजियाबाद को इकॉनोमिक कोरिडोर से जोड़ने की मांग



गाजियाबाद में लोकसभा संसद, मेवर और पांच विधायक भाजपा के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे तक बिना दिल्ली को प्रदूषित किये ले जाया जा सकता है। पुराने अलाइंसेटों को विस्तारित करें हुए इकॉनोमिक जय-जयकर होते हैं। जनरल वीके से तक जय-जयकर होते हैं। गाजियाबाद में उनका मन मिजोरम जाने के बाद भी रसता है। गाजियाबाद से उनका एक लगाव है और ये अकर्कर समय-समय पर दिखाई देता है। हवाई अड्डे से उड़ान की बात हो जा रही है। उनका एक लगाव है और एकर्कर समय-समय पर दिखाई देता है।

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। जनरल वीके सिंह लगाव दो बार गाजियाबाद से सोने लगाव दरहे हैं और केंद्र सरकार के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे तक बिना दिल्ली को प्रदूषित किये ले जाया जा सकता है। पुराने अलाइंसेटों को विस्तारित करें हुए इकॉनोमिक जय-जयकर होते हैं। जनरल वीके के बाद भी रसता है। गाजियाबाद में उनका मन मिजोरम जाने के बाद भी रसता है। गाजियाबाद में उनका एक लगाव है और ये अकर्कर समय-समय पर दिखाई देता है। हवाई अड्डे से उड़ान की बात हो जा रही है। उनका एक लगाव है और एकर्कर समय-समय पर दिखाई देता है।

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। जनरल वीके से एक बात साझा करना चाहता है। मैं अपने पिता के बारे में सोने लगाव की बात की बात चाहता हूं कि मेरे पिता जी के नाम पर विजय नगर साड़े में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए। यह देशराज देशी के पुत्र ने सोने लगाव की बात की बात चाहता है। मैं अपने पिता के बारे में सोने लगाव की बात चाहता हूं कि मेरे पिता जी के नाम पर विजय नगर साड़े में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए।

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। जनरल वीके से एक बात साझा करना चाहता है। मैं अपने पिता के बारे में सोने लगाव की बात चाहता हूं कि मेरे पिता जी के नाम पर विजय नगर साड़े में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए। यह देशराज देशी के पुत्र ने सोने लगाव की बात की बात चाहता है। मैं अपने पिता के बारे में सोने लगाव की बात चाहता हूं कि मेरे पिता जी के नाम पर विजय नगर साड़े में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए।

गाजियाबाद (करंट क्राइम)। जनरल वीके से एक बात साझा करना चाहता है। मैं अपने पिता क

यूएस: छठे दिन में प्रवेश कर गई भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की वार्ता, बढ़ाई गई अधिकारियों के प्रवास की अवधि

वॉशिंगटन | भारत की टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। यह टीम अमेरिका के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए वॉशिंगटन में मौजूद है।

अधिकारियों के प्रवास की अवधि बढ़ी

अधिकारियों के अमेरिका प्रवास की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रतिनिधिमंडल के लिए वार्ता के लिए वहाँ आये थे। वहाँ वार्ता वार्ता 26 जून से शुरू हुई थी। वहाँ वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रॉप्रणाली के समय लागे गए पारस्परिक शुल्क टैरिफ़ की निन्दन अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दोनों देश इस तारीख से पहले वार्ता को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।



प्रस्तावित व्यापार समझौता विफल हुआ तो लगेगा 26 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ़ अधिकारी ने कहा, भारत ने अपनी की कृषि उत्पादों पर टैरिफ़ में छूट देने के मामले में अपना रुख सख्त कर लिया है। भारत चाहता है कि उसके श्रम-प्रधान उत्पादों जैसे वस्त्र, इंजीनियरिंग सामग्री, चमड़ा, रब और अपूर्ण को अमेरिका में टैरिफ़ में छूट दिलाने की मांग कर रहा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत वॉशिंगटन में मंगलवार को छठे दिन में प्रवेश कर गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बातचीत अहम नोड पर पहुंच चुकी है और भारत अपने श्रम-प्रधान उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच दिलाने की मांग कर रहा है।

व्यापार समझौता विफल होता है, तो 26 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क दबावा लागू हो जाएगा। दो अप्रैल को अतिरिक्त व्यापार उत्पादों पर 26 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, अमेरिका का 10 फीसदी मूल टैरिफ़ अब भी लागू है। भारत इस अतिरिक्त 26 फीसदी टैरिफ़ से पूरी छूट चाहता है। भारत ने किसी भी देश के लिए नई खोला डेरी क्षेत्र अमेरिका की ओर डेवरी क्षेत्रों में भी अतिरिक्त टैरिफ़ छूट की मांग कर रहा है। लेकिन ये क्षेत्र भारत के लिए संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ के किसान इसे भूखंडों पर जीविका के लिए खेती करते हैं। इसी कारण ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हैं।

भारत इस अतिरिक्त 26 फीसदी टैरिफ़

मस्क अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौट जाएं, ट्रॉप ने दी टेस्ला की सब्सिडी रोकने की घटकी

वॉशिंगटन | ट्रॉप के बिंग ब्लूटीफुल बिल का विवाद मूल्यांकन कर रहे हैं और बिल का विवाद कर रहे हैं। अब लग रहा है कि ट्रॉप के सब्सिडी की ओर अब उत्तरों में भी मस्क को धमकी दी जाती है। ट्रॉप ने मस्क की कंपनीजों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने की धमकी दी है और अब उत्तरों में भी मस्क अपनी दुकान बंद करें और दक्षिण अफ्रीका वापस लौट जाए।



को इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्ञाना सब्सिडी मिल सकती है और सब्सिडी के बिंग ब्लूटीफुल बिल की नीति अलीचना की ओर साथ ही धमकी दी की जो भी संसद सदस्य अफ्रीका वापस लौटना होगा। कोई और रोल लॉन्च, सैटेलाइट या ट्रैकिंग कारों का उत्पादन नहीं होगा और हमारे देश का बहुत सारा पैसा चुनाव में हार का समाना करना पड़ सकता है। मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'कांग्रेस का हर सदस्य, जो सरकारी खर्च में कटौती और देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज में जाहिए।' ट्रॉप का यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब एलन मस्क ने भी सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'एलन मस्क को राष्ट्रपति ट्रैप के लिए मेरा समर्थन करेंगे उन्हें मैं लालू साल होने वाले प्राइमरी चुनाव में हार का समाना करना पड़ सकता है। मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'कांग्रेस का हर सदस्य, जो सरकारी खर्च में कटौती और देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज में जाहिए।'

बहुत सारा पैसा बचाया जाना चाहिए।' ट्रॉप का यह पोस्ट ऐसे समय इतिहास के बिंग ब्लूटीफुल बिल की धमकी दी है।

गाजा: युद्धविद्याम की कोशिशों के बीच गाजा में आईडीएफ हमला, 74 की नौत, खाना मांग रहे लोगों पर भी बरसाई गोलियाँ

तेल अवीव | एक ओर अमेरिका गाजा में युद्धविद्याम पर वात करने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इत्तावी सेना वहाँ अपने हमले जारी रखे हुए है। सोमवार को आईडीएफ के ताजा हमलों में गाजा में 74 लोग मारे गए। गाजा में अधिकारियों ने बताया कि इत्तावी सुरक्षा बलों ने सोमवार को गाजा में बुल्डॉप ऐप्लीकेशन पर जहाँ हवाई हमले किए वहीं, खाना पाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों पर गोलियाँ भी बरसाई हैं।



मरने वालों ने बच्चे और नहिलाएं भी शामिल

जानकारी के मुताबिक, इस्माइली सुरक्षा बलों ने गाजा स्थिरी के अल-बक्वा कैफे को निशाना बनाया। जहाँ 30 लोग मारे गए।

किया जब महिलाओं और बच्चों सेवा के प्रमुख फारेस अवाद ने की भीड़ थी। अलीन अब्दुल अतीला, जो कि हमले के समय कैफे में ही थे, उत्तरों बताया कि बिना किसी चेतावनी के आईडीएफ के एक युद्धक विमान ने अचानक हमला कर दिया। हमले के दौरान ऐप्लीकेशन पर गोलियाँ भी बरसाई हैं। जंग के दौरान भी चालू था कैफे गैरतलब है कि आईडीएफ द्वारा लगा जैसे कि वहाँ भूक्षण आ गया हो। उत्तरी गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन और एब्युलेस

सेवा के प्रमुख फारेस अवाद ने बताया कि इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। अवाद ने बताया कि घायलों में से कई को हालत गंभीर है। इनमें स्थाइली और बच्चे भी शामिल हैं।

कैफे के अलावा, गाजा पट्टी में राहत समझी पाने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीनी लोगों पर भी अतिरिक्त चालू था। इस हमले में 23 लोग मारे गए। इसके अलावा, ऐप्लीकेशन ने बताया कि गाजा शहर की सड़क पर हुए दो अन्य हमलों में 15 लोग मारे गए।

जंग के दौरान भी चालू था कैफे गैरतलब है कि आईडीएफ द्वारा लगा जैसे कि वहाँ भूक्षण आ गया हो। उत्तरी गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय निशाना बनाया गया वह जंग के दौरान लगा जैसे कि वहाँ भूक्षण आ गया हो। उत्तरी गाजा में जून से जून तक भी चालू था कैफे गैरतलब है कि आईडीएफ द्वारा लगा जैसे कि वहाँ भूक्षण आ गया हो।

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर फिर अलापा मध्यस्थता कोर्ट का राग, भारत से की ये अपील

इस्लामाबाद | पाकिस्तान ने एक बार फिर हेंग स्थित मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को राग अलापत हुए। भारत से सिंधु जल संधि का पालन करने की अपील की। हालांकि भारत ने स्थित कर दिया कि उसने इस संधि के विवादों को सुलगानी के मामलों में मध्यस्थता कोर्ट के अधिकार को कमी मान्यता नहीं दी है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अलापा सिंधु जल संधि का राग पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बार फिर हेंग स्थित कोर्ट के पूर्क फैसले को संबंध में जारी कर रहा है। यह फैसले से आग्रह करते हैं कि इस संधि का समान्य परिचलन तक तालाल आरंभ करे और इस संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी कर कहा, मध्यस्थता कोर्ट ने 27 जून के फैसले में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष को सही ठारखारा करने के लिए फैसले से सामान्य अप्रैल के अलावा जल संधि कोर्ट के पूर्क फैसले का स्वामान तक तालाल आरंभ करे और इस संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें।



जून के फैसले में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष को सही ठारखारा करने के लिए फैसले में कहा गया था। सोमवार कोर्ट के पूर्क फैसले का स्वामान तक तालाल आरंभ करे और इस संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान में सुनवाई और जुड़ा मध्यस्थता न्यायालय का पूर्क अवार्ड पूरी तरह तैयार किया है। क्योंकि सिंधु जल संधि-1960 के तहत गठित मध्यस्थता न्यायालय ही अवैध है। भारत एक रफरफा रूप से इसे स्थगित नहीं कर सकता। राष्ट्रों का आकलन अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अलावा जारी दी है।

श्रीलंकाई नौसेना ने सात भारतीय मछुआरों को किया गया अपराधिक न्यायालय पर साइबर अपराध, लगाया अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप

नई दिल्ली | श्रीलंकाई नौसेना ने सोमवार कर लिया है और उनके नाव जल्द कर लिए गए हैं। इन पर श्रीलंका की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप है। यह घटना तलाइमानार क्षेत्र में हुई और वहाँ तो एक हानि में एसोसिएटी एस्प्रेस ने गाजा मामला है। नौसेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रविवार को भी हुई थी गिरफ्तारी

प्रवेश करने के कारण अक्सर गिरफ्तार किया जाता है। यह मछुआरों का

